



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 125-2017/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017
(26 आषाढ़, 1939 शक)

क्रमांक	विषय वस्तु	विधायी परिशिष्ट	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम		
	कुछ नहीं		
भाग II	अध्यादेश		
	कुछ नहीं		
भाग III	प्रत्यायोजित विधान		
	अधिसूचना संख्या का०आ०-51/ह०अ० 32/2014/धा० 19/2017, दिनांक 18 जुलाई, 2017 — हरियाणा वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम, 2017 (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)		473-481
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन		
	कुछ नहीं।		

भाग—III**हरियाणा सरकार****वित्त विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 18 जुलाई, 2017

संख्या का०आ०-51/ह०अ० 32/2014/धा० 19/2017.— हरियाणा वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2013 (2014 का हरियाणा अधिनियम 32), की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम हरियाणा वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम 2017, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम ।
2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; परिभाषाएं ।
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा (वित्तीय स्थापना में) निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2013; (2014 का 32);
 - (ख) "परिसम्पत्ति" से अभिप्राय तथा इसमें शामिल है, ऐसे व्यक्ति की चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति, शेयर, अन्य प्रतिभूतियां तथा बैंक में जमा या किसी व्यक्ति से देय धन ;
 - (ग) "प्ररूप" से अभिप्राय है, नियमों से संलग्न प्ररूप ।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त, किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः इस अधिनियम में दिए गए हैं।
3. (1) प्रत्येक वित्तीय स्थापना, जो इन नियमों के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से हरियाणा राज्य में ऐसे रूप में अपना कारबार प्रारम्भ करती है या संचालित करती है, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर प्ररूप-1 में जिला के कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करेगा। वित्तीय स्थापना की रिपोर्ट। धारा 19.
 - (2) प्रत्येक वित्तीय स्थापना जो इन नियमों के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से पूर्व ऐसे रूप में अपना कारबार संचालित कर रही है, पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्ररूप -1 में जिले के कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को ऐसी रिपोर्ट करेगी।
 - (3) प्रत्येक वित्तीय स्थापना प्ररूप-1 में प्रस्तुत किए गए किसी ब्यौरे के सम्बंध में, किसी परिवर्तन की दशा में, परिवर्तन किए जाने के बाद सात दिनों की अवधि के भीतर जिले के कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करेगी।
4. सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता और गवाहों, यदि कोई हो, या किसी भी व्यक्ति या वित्तीय स्थापना के उस पदाधिकारी या कर्मचारी की जांच कर सकता है, जो उसकी राय में वित्तीय स्थापना के संबंध में कोई जानकारी देने में सक्षम हो, जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया है तथा ऐसी जांच लिखित में अभिलिखित की जाएगी। शिकायतकर्ता तथा साक्षियों इत्यादि की जांच-पड़ताल। धारा 6.
5. प्रत्येक वित्तीय स्थापना, वित्त वर्ष की प्रत्येक त्रैमासिक की समाप्ति के बाद एक मास के भीतर उसमें ब्यौरे तथा राज्य के भीतर तथा बाहर उसके दी गई धनराशि के निवेश की प्रत्येक अवस्थिति दर्शाते हुए प्ररूप-II में जिले के कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक, जिसकी अधिकारिता के भीतर कारबार का स्थान अवस्थित है, को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगी तथा जहां वित्तीय स्थापना के राज्य में एक से अधिक स्थानों पर कारबार अवस्थित है, की दशा में जिले के कलक्टर या पुलिस अधीक्षक जिसकी अधिकारिता के अधीन उस द्वारा यथा घोषित मुख्य कार्यालय अवस्थित है, को विवरणी प्रस्तुत करेगी। वित्तीय स्थापना द्वारा विवरणी। धारा 19.
6. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट एक मास की अवधि के भीतर सरकार को ऐसी शिकायत भेजेगा । सरकार को शिकायत भेजने हेतु समय अवधि। धारा 4(3).

जब्त की गई
धनराशि तथा कुर्क
सम्पत्ति तथा उनके
निपटान के रिकॉर्ड
का रख-रखाव।
धारा 4.

7. (1) जहाँ अधिनियम की धारा 4 के अधीन कुर्क की गई कोई सम्पत्ति कार्यवाही संस्थित करने से पूर्व शीघ्रता से या प्राकृतिक रूप से विघटन के अधीन है तो सक्षम प्राधिकारी सार्वजनिक नीलामी द्वारा या अन्यथा ऐसी सम्पत्ति को बेच सकता है और बिक्री आगामों को अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3)के खण्ड (ख) में यथा वर्णित बैंक खाते में जमा करवाएगा और पदनामित न्यायालय को इसकी सूचना देगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी अधिनियम 10 की उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन पदनामित न्यायालय के आदेश द्वारा इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त आय, विक्रय आगमों या उप नियम—(1) के अधीन सम्पत्ति की बिक्री तथा प्राप्त, प्रबन्धित और निपटान की गई सम्पत्ति के लिए प्रोदभूत खर्च का रिकॉर्ड भी रखेगा और समय-समय पर, पदनामित न्यायालय को इसको प्रस्तुत करेगा।

चूककर्ता वित्तीय
स्थापना के
लेखा-पुस्तकों/
कागजात तथा
दस्तावेजों की
सुरक्षित अभिरक्षा।
धारा 6.

8. सक्षम प्राधिकारी पदनामित न्यायालय के अन्तिम आदेश जारी होने तक तथा अपील के मामले में, जैसी भी स्थिति हो, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के आगामी आदेशों तक चूककर्ता वित्तीय स्थापना के सभी अभिलेखों/पुस्तकों/कागजातों और दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा।

चूककर्ता वित्तीय
स्थापना के लेखों का
लेखा-परीक्षण।
धारा 19.

9. सक्षम प्राधिकारी प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से चूककर्ता वित्तीय स्थापना के तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि विवरणों को लेखा-परीक्षित करवाने के लिए उत्तरदायी होगा।

सम्पत्ति के निर्धारण
के लिए प्रक्रिया।
धारा 7.

10. (1) सक्षम प्राधिकारी चूककर्ता वित्तीय स्थापना की परिसम्पत्तियों निक्षेप तथा दायित्वों के निर्धारण के लिए पंजीकृत मूल्यांकक नियुक्त करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त पंजीकृत मूल्यांकक राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के पैनल पर होगी।

(3) भूमि के मूल्यांकन के मामले में, बाजार कीमत, निर्धारण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा किसी भी दशा में, बाजार कीमत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कलक्टर दर से कम नहीं होगी।

(4) अन्य परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु, बाजार कीमत अवमूल्यन को घटाकर या परिसम्पत्तियों के पुनः मूल्यांकन का उपयोग किया जाएगा।

प्ररूप - I

(देखिए नियम 3)

वित्तीय स्थापना की रिपोर्ट

सेवा में

कलक्टर..... (जिला)

तथा

पुलिस अधीक्षक (जिला)

1.	वित्तीय स्थापना का नाम:	
2.	पंजीकरण प्राधिकारी का नाम तथा पता:	
3.	विनियामक का नाम तथा पता:	
4.	विनियामक के पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या तथा दिनांक	
5.	तिथि सहित पंजीकरण/निगमीकरण संख्या	
6.	ऐसा कारबार करने के प्राधिकार के बारे में विस्तृत विवरण:	
7.	राज्य का नाम जिसमें वित्तीय स्थापना पंजीकृत है:	
8.	पूरा पता: (क) पंजीकृत कार्यालय, पिन नम्बर, दूरभाष नम्बर (ख) मुख्य शाखा कार्यालय (यदि कोई हो)	
9.	वित्तीय स्थापना के मामलों के प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति * का नाम तथा पता (वर्तमान तथा स्थाई) तथा पैन नम्बर :	1 श्री 2 श्री
10.	**शाखाओं/कार्यालयों की संख्या:	
11.	वित्तीय स्थापना के लेखा-परीक्षक का/के नाम तथा पता:	
12.	वित्तीय स्थापना (स्थापनाओं) के, बैंकर का/के नाम तथा पता:	
13.	वित्तीय स्थापना के वित्तीय मामलों को देखभाल करने वाले व्यक्ति का नाम, पता (वर्तमान तथा स्थाई) तथा पदनाम	

प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट में दिए गए ब्यौरे/सूचना सत्यापित कर दी गई है तथा सभी मामलों में सही तथा पूर्ण पाई गई है।

दिनांक:

स्थान:

प्रबन्धक/प्रबन्धक निदेशक/

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

- * यदि वित्तीय स्थापना के मामलों के प्रबन्धन के लिए दो से अधिक व्यक्ति उत्तरदायी हैं, तो नाम तथा पता दर्शाते हुए प्ररूप से संलग्न सूची दे सकते हैं।
- ** वित्तीय स्थापना का शाखा कार्यालय/कार्यालयों में अवस्थित है/हैं के स्थान/स्थानों का नाम तथा पता दर्शाते हुए सूची संलग्न की जानी चाहिए।

प्ररूप -II
(देखिए नियम 5)
त्रैमासिक विवरणी

वित्तीय वर्ष
त्रैमासिक की समाप्ति.....

1.	वित्तीय स्थापना का नाम।	
2.	पंजीकरण प्राधिकारी का नाम तथा पता।	
3.	तिथि सहित पंजीकरण/ निगमन संख्या।	
4.	वित्तीय स्थापना का पैन नंबर और प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष/प्रबंध हिस्सेदार/सी.ई.ओ./मालिक का पैन और आधार नंबर।	
5.	निदेशकों/भागीदारों/मालिक के नाम तथा पते।	
6.	प्रबंधक/अध्यक्ष/प्रबंध भागीदार/सीईओ/मालिक के नाम तथा पते (वर्तमान और स्थायी)।	
7.	कारबार का स्वरूप।	
8.	बैंकों के नामों, खाता नम्बरों और बैंकर के पते का विवरण।	
9.	तिमाही की समाप्ति पर बैंकवार और लेखावार शेष राशि।	
10.	तिमाही की समाप्ति पर वित्तीय स्थापना की चल/अचल सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण।	
11.	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र।	
12.	हरियाणा राज्य में तिमाही के दौरान जमाकर्ताओं से प्राप्त राशि।	
13.	हरियाणा राज्य में तिमाही के दौरान ऋणों समेत अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि।	
14.	हरियाणा राज्य से प्राप्त राशि में से तिमाही के दौरान राशि का प्रयोग/निवेश।	
15.	ऐसे उपयोग/निवेश/खर्च का विवरण।	
16.	खसरा नंबर और प्लॉट नंबर इत्यादि सहित राज्य के भीतर और राज्य से बाहर ऐसे निवेश का क्षेत्र और अवस्थिति।	
17.	तिमाही के दौरान सृजित/अर्जित परिसम्पत्तियों का विवरण।	
18.	राज्य के भीतर जमाकर्ताओं को पेश लाभ की न्यूनतम दर।	
19.	राज्य के भीतर जमाकर्ताओं को पेश लाभ की अधिकतम दर।	
20.	जमा राशि पर लाभ की ओर भुगतान के, ब्यौरे जैसे कि ब्याज, लाभांश या कई अन्य सेवाएँ।	
21.	तिमाही के दौरान राज्य के भीतर निवेशकों/जमाकर्ताओं को परिपक्वता राशि सहित वापस की गई राशि का विवरण और जहां यह संगृहीत थी।	
22.	तिमाही की समाप्ति पर जमाकर्ताओं को भुगतान योग्य राशि।	
23.	तिमाही के दौरान निवेशकों/जमाकर्ताओं को सौंपी गई सम्पत्ति जैसे कि भूमि/प्लॉट या फ्लैट या अन्य सेवाएँ।	
24.	तिमाही के अंत में प्रबंध निदेशकों/सीईओ/ भागीदारों/मालिकों के बैंक अतिशेषों को शामिल करते हुए चल और अचल परिसम्पत्तियों का विवरण।	

टिप्पण.-

- (1) नई निगमित वित्तीय स्थापना के मामले में, जिसके पास इसका लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र नहीं है, वित्तीय स्थापना की नियत तथा चालू परिसम्पत्तियों के विस्तृत ब्यौरे देते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट से सम्यक् रूप से सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए।
- (2) यदि अपेक्षित हो, तो अनुलग्नक के रूप में अतिरिक्त कागजात संलग्न किये जा सकते हैं।

पी. राधावेन्द्रा राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

*(Authorised English Translation)***HARYANA GOVERNMENT****FINANCE DEPARTMENT****Notification**

The 18th July, 2017

No. S.O.-51/H.A. 32/2014/S. 19/2017— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Haryana Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 2013 (32 of 2014), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Rules, 2017. Short title.
2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “Act” means the Haryana Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act 2013 (32 of 2014);
 - (b) “asset” means and includes both movable and immovable property of such person, shares, other securities and money deposited in the bank or due from any person;
 - (c) “form” means form appended to these rules.
- (2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.
3. (1) Every financial establishment which commences or carries on its business as such in the State of Haryana on the date of notification of these rules in the Official Gazette shall make a report to the Collector and the Superintendent of Police of the district in Form-I within a period of fifteen days. Report of financial establishment. section 19
 - (2) Every financial establishment which has been carrying on its business as such prior to the date of notification of these rules in the Official Gazette shall make such report to the Collector and the Superintendent of Police of the district in Form-I within a period of fifteen days.
 - (3) Every financial establishment shall report to the Collector and Superintendent of Police of the district, in case of any change in respect of any particular furnished in Form-I within a period of seven days after the change has taken place.
4. The competent authority may examine the complainant and the witnesses, if any, or any person or office bearer or employee of financial establishment who in his opinion shall be able to give any information about the financial establishment in respect of which an order of attachment has been made by District Magistrate and such examination shall be recorded in writing. Examination of complainant and witnesses etc. section 6
5. Every financial establishment shall furnish quarterly return within one month after the expiry of each quarter of a financial year in Form-II showing details therein and the location of investment of moneys made by it within and outside the State to the Collector and Superintendent of Police of the district within whose jurisdiction the place of business is located and in case where the financial establishment has more than one place of business in the State, shall furnish such return to the Collector or Superintendent of Police of the district under whose jurisdiction its head office as declared by him is located. Return by the financial establishment. section 19
6. On receiving a complaint under clause (1) of sub section (1) of section 4 of the Act, the District Magistrate shall forward such complaint to the Government within a period of one month. Time period for forwarding of complaint to Government. section 4(3)

Maintenance of record of money and property attached and disposal thereof. section 4

7. (1) Where any property attached under section 4 of the Act is subject to speedy or natural decay before institution of the proceeding, the competent authority may sell such property by public auction or otherwise and credit the sale proceeds in a bank account as mentioned in clause (b) of sub-section (3) of section 6 of the Act and shall intimate the same to the designated court.

(2) The competent authority shall maintain the record of all the income and sale proceeds received on sale of property so attached by the order of the designated court under sub-section (4) or sub-section (6) of section 10 of the Act or sale of property under sub-rule (1) and expenditure incurred for the property received, managed and disposed off and shall furnish the same to the designated court, from time to time.

Safe custody of books, papers and documents of defaulting financial establishment. section 6

8. The competent authority shall ensure safe custody of all the records/books/papers and documents of the defaulting financial establishment till the issuance of final order of the designated court and in case of appeal, till further orders of the High Court or Supreme Court, as the case may be.

Auditing of accounts of defaulting financial establishment. section 19

9. The competent authority shall be responsible for getting the balance sheet and profit and loss statements of the defaulting financial establishment audited through a Chartered Accountant duly appointed for the purpose.

Procedure for assessment of property. section 7

10. (1) The competent authority shall appoint a registered valuer for assessment of asset, deposit and liabilities of the defaulting financial establishment.

(2) The registered valuer, so appointed under sub-rule (1) shall be from the panel of State Government or the Central Government.

(3) In the matter of valuation of land, the market price shall be used for assessment and in no case the market price shall be less than the Collector rate, as notified by the Government.

(4) For the valuation of other assets, the market price less the depreciation or the revaluation of assets be used.

FORM-I*(See rule 3)***Report of Financial Establishment**

To

The Collector,.....(District)

and

Superintendent of Police.....(District)

1	Name of the Financial Establishment:	
2	Name and address of Registering Authority:	
3.	Name and address of the Regulator:	
4.	Date and Registration Certificate Number of the Regulator:	
5.	Registration /Incorporation Number with date:	
6.	State in detail about the authority to carry on such business:	
7.	Name of the State in which the Financial Establishment is registered:	
8.	Full address: (i) Registered Office, PIN No., Phone No. (ii) Main Branch Office (if any):	
9.	Name, address (present and permanent) and PAN number of every Person * responsible for management of affairs of the Financial Establishment:	(1) Sri..... (2) Sri.....
10	** Number of Branches/Offices:	
11.	Name(s) of the Financial Establishment's Auditor and address:	
12.	Name(s) of the Financial Establishment's Banker(s) Name and addresses:	
13.	Name, address (present & permanent) and designation of the person looking after financial matters of the Financial Establishment:	

Certified that the particulars/ information furnished in the report have been verified and found to be correct and complete in all respects.

Date:

Place:

Signature of Manager/Managing

Director/authorised official

Name:

Designation:

* If more than two persons are responsible for the management affairs of the Financial Establishment they may give a list showing name and address appending to this Form.

** A list showing the names and address of the place(s) where the Branch Office(s) of the Financial Establishment is/are situated should be enclosed.

FORM-II*(See rule 5)***QUARTERLY RETURN**

Financial Year

Quarter Ending

1.	Name of the Financial Establishment.	
2.	Name and Address of Registering Authority.	
3.	Registration/ Incorporation number with Date.	
4.	PAN numbers of the Financial Establishment and PAN & Aadhaar Number of Managing Director/ President/Managing Partner/Chief Executive Officer/ Proprietor.	
5.	Names and addresses of Directors/Partners/ Proprietor.	
6.	Names and addresses (present and permanent) of Managing Director / President /Managing Partner/Chief Executive Officer/ Proprietor.	
7.	Nature of business.	
8.	Details of Bank Names, account numbers and addresses of the Banker(s).	
9.	Bank-wise and Account-wise Balance as on the end of the quarter.	
10.	Details of movable / immovable assets of the Financial Establishment as on the end of the quarter.	
11.	Copies of latest Audited Balance Sheet.	
12.	Amount received during the quarter from the Depositors in the State of Haryana.	
13.	Amount received from other sources including loans during the quarter in the State of Haryana.	
14.	Amount utilized / invested and spent during the quarter from the amount mobilised in the State of Haryana.	
15.	Details of such utilization / investment/ spent.	
16.	Area and location of such investment within and outside State with details of Khasra number, Plot number etc.	
17.	Details of assets created / acquired during the quarter.	
18.	Minimum rate of return offered to depositor within the State.	

19	Maximum rate of return offered to depositor within the State.	
20.	Details of payments towards return on deposited amount such as interest, dividend or any other services.	
21.	Details of amount refunded including maturity amount to the investors/depositors during the quarter within the State from where it was collected.	
22.	Amount payable to the depositors at end of the quarter.	
23	Details of properties such as land/ plots or flats handed over or other services rendered to the investors/depositors during the quarter.	
24	Details of movable/immovable assets including bank balances of Directors/Managing Directors/Chief Executive Officer/Partner/Proprietor as on the end of the quarter.	

Note.—

- (1) In case of a newly incorporated financial establishment, which does not have its audited balance sheet, duly attested certificate from a Chartered Accountant giving details of the fixed and current assets of the financial establishment be enclosed.
- (2) If required, additional sheets may be enclosed as *Annexure*.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.